



एनआईसी तेलंगाना: तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी (टी.एस.जे.ए.) में जिला न्यायालय प्रणाली अधिकारियों और प्रशासकों के लिए एन.आई.सी. तेलंगाना अधिकारियों द्वारा कार्यशाला – 18 अक्टूबर 2025

जिला न्यायालय प्रणाली अधिकारियों और प्रणाली प्रशासकों के लिए तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा **18 अक्टूबर 2025** को **तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी, हैदराबाद** में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। तेलंगाना उच्च न्यायालय के तकनीकी कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रशिक्षण का आयोजन माननीय ई-कमेटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, चल रहे "ई-कोर्ट्स क्षमता निर्माण कार्यक्रम" के तहत, टीएसजेए के समन्वय में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), तेलंगाना के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के अनुरोध पर किया गया था।

सत्र का उद्देश्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखरखाव, डेटा प्रतिकृति और निगरानी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और एलएएन कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बढाना था।

निम्नलिखित एनआईसी तेलंगाना अधिकारियों ने सत्रों का नेतृत्व किया और अपने-अपने विषयों पर प्रस्तुति दी:

- 1. **सुश्री श्रीलता गोरला,** संयुक्त निदेशक (आईटी) और **सुश्री गेदाला सुजाता**, सहायक निदेशक (आईटी) डेटा रेप्लिकेशन एंड मॉनिटरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी
- 2. श्री शिव रामुलु, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) और श्री के.वी. सूर्य नारायण, उप निदेशक (आईटी) हार्डवेयर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस
- श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक (आईटी) सर्वर एंड नेटवर्क एडिमनिस्ट्रेशन
- 4. सुश्री एम. सुभा, निदेशक (आईटी) और श्री नीलेश कुमार, संयुक्त निदेशक (आईटी) सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट



बाएँ से दाएँ

- 1. सुश्री एम. सुभा , निदेशक (आईटी)
- 2. सुश्री गेदाला सुजाता, सहायक निदेशक (आईटी)
- 3. सुश्री श्रीलता गोरला, संयुक्त निदेशक (आईटी)
- 4. श्री शिव रामुलु, वरिष्ठ निदेशक (आईटी)
- 5. श्री नीलेश कुमार, संयुक्त निदेशक (आईटी)
- 6. श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक (आईटी)
- 7. श्री के.वी. सूर्य नारायण, उप निदेशक (आईटी)













प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ:





























कार्यशाला ज्ञान साझा करने और व्यावहारिक शिक्षा के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में काम करती है, जिससे प्रतिभागियों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और पूरे राज्य में ई-कोर्ट्स बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन का समर्थन करने में मदद मिलती है।











